



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 590] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 7, 1989/कार्तिक 16, 1911
No. 590] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 7, 1989/KARTIKA 16. 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या ही आती है जिससे कि यह भलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

कार्मिक, साके क्षिकायत आर पैक्सन मन्त्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

प्रधिकारी

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1989

का. का. नि. 967(प) — भारतीय पुस्तिक सेवा (कर्त्ता) विभागी, 1954 के विभाग 9 के उप-विभाग (1) के अनुमति में और अधिन भरतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) को धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों तथा संघ नोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात नियमित पुस्तिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विभागी, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एम्बेड्डर नियन्त्रित विभाग बनाती है, अर्थात् —

1 (1) इन विभागों का नाम भारतीय पुस्तिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) द्वितीय मंत्रीधन, विभागी, 1989 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होती।

2 भारतीय पुस्तिक नेत्र (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विभागी, 1955 में —

(1) विभाग 2 के उप-विभाग (1) के खण्ड (ट) के पश्चात नियन्त्रित खण्ड या मिल किया जाए, अर्थात् —

“(1) वर्ष से तस्य अप्रैल के प्रथम दिन से ग्राम्य होकर अनुवर्ती वर्ष के मार्च के 31वें दिन को समाप्त अवधि से है।”

(2) विभाग 3 में उप-विभाग (1) के लिए नियन्त्रित उप-विभाग प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् —

“(1) राज्य मर्का या किसी संयुक्त संघर्ष के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें आयोग का अध्यक्ष समिति से होता है और जहां पर आयोग उपरियोग नहीं हो पाता, आयोग का कोई अन्य सदस्य इसका प्रतिनिधित्व करता है और नियन्त्रित गद्दी होते हैं, अर्थात् —

(क) संगठन संवर्गी के अनियन्त्रित अन्य राज्य

(i) मुख्य मंत्रिव,

(ii) सरकार के कम से कम मंत्रिव के रैंक का अधिक री गृह विभाग का प्रभारी,

(iii) महा निदेशक तथा पुस्तिक महा निरीक्षक,

अधिकारी

जहा पर महानिदेशक तथा पुलिस महानीशक का कोई सदर्ग पद विद्यमान नही है तो पुलिस महानीशक,

- (iv) सेवा का कोई सदर्ग जो कम से कम पुलिस उप महानीशक के रैक के अंतर्गत है, अर्थात्
- (v) भारत सरकार का कोई मनोनीत मदर्ग जिसका रैक सयुक्त मन्त्रियों से कम न हो।
- (vi) अस्त्रणालय प्रदेश-गोवा-मिजोरम-मध्य राज्य थेट्रो के अनिवार्य मयुक्त मंत्रियों के लिए
- (i) मंथटक राज्यों की सरकारों के मुख्य मन्त्रियों
- (ii) मंथटक राज्यों के महा निदेशक तथा पुलिस महानीशक;

या

जहां पर महा निदेशक तथा पुलिस महानीशक का कोई सदर्ग पद विद्यमान नही है, वहां मंथटक राज्यों का पुलिस महानीशक,

- (iii) भारत सरकार का कोई मनोनीत मदर्ग जिसका रैक कम से कम सयुक्त सचिव स्वर का हो।

टिप्पणी.—अस्त्रणालय प्रदेश—गोवा—मिजोरम—मध्य राज्य थेट्रों के मयुक्त मंत्रियों के लिए समिति का गठन उपर्युक्त मंत्रियों के लिए मयुक्त मंत्रियों प्राधिकारियों से परामर्श करके पृथक रूप से निर्धारित किया जाएगा।

३. विनियम ५ में—

- (क) जहां कहीं “जनवरी का पहला दिन” शब्द अपना वहां “अप्रैल का पहला दिन” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ख) उप-विनियम (i) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(1) प्रथेक समिति भी बैठक अधिकारी के अधिकारी के अन्तर्गत पर होगी और इसके द्वारा राज्य सिविल सेवा के लिए अदर्गों की सूची तैयार की जाएगी जिन्हें इसके द्वारा सेवा के पोदोशपि के लिए उपयुक्त समझा जाना है। सूची में समिक्षित विषय जाने वाले राज्य सिविल सेवा के मदर्गों को सख्ता की गणना भलो नियमों के नियम ५ के अधीन उनके लिए उपलब्ध पदों से सूची तैयार होने की तारीख से १२ महीनों की अवधि के दौरान प्रत्येक सम विकारों के रूप में की जाएगी तथा उसमें उम सलाह का २० प्रतिशत अवधार दो पद, इनमें से जो भी अधिक हो जोड़ दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण—मयुक्त मंत्रियों के मामले में, प्रथेक राज्य पुलिस सेवा से सम्बन्धित एक पृथक चयन सूची तैयार की जाएगी, प्रथेक चयन सूची का अवार उपयुक्त दर्शायी गई पद्धति के अनुसार निर्धारित किया जा रहा है।

- (ग) उप-विनियम (2क) और उपके अधीन आने वाले स्पष्टीकरण विस्तृत हो जाएगे।
- (घ) उप-विनियम (5) में, “राज्य पुलिस सेवा” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“राज्य पुलिस सेवा”,

वशतें कि सूची में इस नरह से समिक्षित किसी भी अधिकारी या नाम अनलिम समझा जाएगा, यदि राज्य सरकार ऐसे अधिकारी के संवध में स्थनिष्ठा प्रमाण पत्र देने से इकार कर-

देने हैं और उन्होंने इन्हें कोई वार्ता द्वारा प्रमाणित है अथवा लम्बित है अथवा उसके विस्तृत रूप से भरकार के द्यान में को प्रतिक्ल बात शाई हो।

४. विनियम ६ के बाद निम्नलिखित विनियम जारी जाएगा।

“६क राज्य सरकार विनियम ६, में उल्लिखित सूची की एक प्रति केन्द्रीय सरकार का भी भेजेगी और केन्द्रीय सरकार समिति की सिफारिशों पर ग्राहयोग को अपनी टिप्पणिया भेजेगी।”

५. विनियम ७ में—

- (क) उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्—

“(1) आयाम समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेंगे इसके माध्यम से

(क) विनियम ६ के अन्तर्गत राज्य सरकार से प्राप्त दस्तावेजों

(ख) केन्द्रीय सरकार की टिप्पणी समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेंगे तथा जब तक वह कोई परिवर्तन अवश्यक न मानते सूची को अनुमोदित करेंगा।”

(घ) उप-विनियम (1) में—

- (i) पहले परन्तुक से पूर्व, निम्नलिखित जोषा ज ०३, अर्थात्— बाणी के विनियम ५ के अन्तर्गत नई सूची तैयार करने वाली नई समिति की बैठक के पश्चात् विनियम ५ के अन्तर्गत सेवा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी।

(ii) प्रथम परन्तुक से ‘गर्ते यह है कि’ शब्द के स्थान पर “आगे गर्ते यह है कि” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

६. विनियम ४ में—

- (क) उप-विनियम (1) में परन्तुक के बाद निम्नलिखित परन्तुक भेजे जाएंगे अर्थात्—

“आगे यह भी गर्ते है कि किसी ऐसे अधिकारी के मामले में जिसका नाम विनियम ५ के उप-विनियम (5) के परन्तुक के अधीन अनलिम स्थान में से चयन सूची में शामिल किया गया है उसकी नियुक्ति जिस प्रवधि तक चयन सूची वैध रहती है उस प्रवधि के दौरान राज्य सरकार की सिफारिशों पर ग्राहयोग द्वारा उसके नाम का बिना शयन अनुमोदित होने के बाद की जाएगी किया जाएगा और प्रतिकारी का नियुक्ति करने वाले गमय जो कि चयन सूची के किसी एवं अधिकारी में कनिष्ठ हो जिसका नाम अनलिम रूप में चयन सूची में शामिल कर लिया गया हो अनलिम रूप में शामिल किया गया एवं अधिकारी वे लिए एक पद लियन गया होंगा।

आगे यह भी गर्ते है कि जिस मामले में चयन सूची के किसी प्रधिकारी की नियुक्ति की बाती है और वह सेवा में नियुक्ति के लिए अनिष्ट जाहिर कर देता है और अन्तिम राज्य सरकार नेतृत्व रेक्ट्रीय सरकार को सूचित कर देता है तो चयन सूची में उसके कनिष्ठ अधिकारियों को, ऐसे अधिकारी के लिए कोई भी पद ग्राहक्षित किया बिना नियुक्ति कर दिया जाएगा। उसे चयन सूची में सेवा में नियुक्ति का कोई हक प्राप्त नही होगा।”

- (घ) उप-विनियम (2) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(2) उन स्थितियों को छोड़कर जब कि राज्य मिक्रिल सेवा के किसी सदर्ग के नाम के चयन सूची में शामिल किए जाने से

लेकर प्रस्तावित नियूक्ति को तारीख के बाब्त का यथापि के दौरान राज्य मिशन सेवा के मद्द्य के काम के स्तर में कोई गिरावट आ गई हो या कोई ऐसा अन्य अधार हो जिसके कारण राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार की राय में उसे सेवा में नियूक्ति के लिए अनुपयुक्त माना गया हो, ऐसी नियूक्तियों से पुर्व सामान्यतः आयोग से परामर्श करना जरूरी नहीं होगा।”

7 विनियम 9 के बाद निम्न जोड़ा जाएगा, अर्थात् —

“9 क. कतिपय मामले में नियूक्ति न किए जाने के बारे में केन्द्रीय सरकार की व्यक्तिया —

इन विनियमों या विनियम 9(1) के अधीन सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा की गई मिफारिशों में जो कुछ कहा गया है उस सब के बाबजूद केन्द्रीय सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम चयन सूची में शामिल है नियूक्ति न करने का अधिकार रखती है बताते कि उसकी राय में ऐसा करना लोक हित की दृष्टि से आवश्यक अथवा समयोजित हो।

लेकिन शर्त यह है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा कोई भी निर्णय सब लोक सेवा आयोग से परामर्श किए बिना नहीं लिया जाएगा।”

8 अनुसूची को विलोपित किया जाएगा।

टिप्पणी—मूल विनियम अधिसूचना सं. 14/2/54-अ. भा. से. (II) तारीख 6-6-1955 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

तथाशब्दात् उहें निम्नलिखित द्वारा मंशोद्धित किया गया —

- 1 13/21/56—अ. भा. से. (III) तारीख 28-2-58
2. 13/10/57-अ. भा. से. (III)—डी तारीख 29-7-58
3. 17/19/58—अ. भा. से. (III)—बी तारीख 2-6-59
4. 10/5/61—अ. भा. से. (I) तारीख 1-9-61
5. 27/48/64—अ. भा. से. (III)-II तारीख 11-12-64
6. 27/28/64—अ. भा. से. (III)-बी तारीख 24-5-60
7. 14/25/65—अ. भा. से. (III) तारीख 7-2-66
8. 27/42/64—अ. भा. से. (III) तारीख 31-3-67
9. 13/4/67—अ. भा. से. (I)-5 तारीख 29-12-67
10. 17/5/68—अ. भा. से. (III)-बी तारीख 24-5-69
11. 17/19/58—अ. भा. से. (III)-बी तारीख 2-6-69
12. 16/1/68—अ. भा. से. (III)-बी तारीख 9-4-70
13. 16/5/70—अ. भा. से. (III) तारीख 21-9-71
14. 13/4/71—अ. भा. से. (I) तारीख 11-1-72
15. 1/1/72—अ. भा. से. (I)-बी तारीख 12-10-72
16. 11/1/72—अ. भा. से. (I)-बी तारीख 22-5-73
17. 11/2/73—अ. भा. से. (I)-डी तारीख 12-9-73
18. 11/1/73—अ. भा. से. (I)-बी तारीख 19-2-74
19. 11039/2/76—अ. भा. से. (I)-बी तारीख 20-4-76
20. 11039/6/76—अ. भा. से. (I)-बी तारीख 30-9-76
21. 11039/1/76—अ. भा. से. (I)-बी तारीख 11-4-77
22. 11039/6/76—अ. भा. से. (I)—डी तारीख 3-6-77
23. 11039/2/76—अ. भा. से. (I)-ए तारीख 3-10-77
24. 11039/21/76—अ. भा. से. (I)-बी तारीख 1-6-78

23. 28012/20/71—अ. भा. से. (I)-बी तारीख 3-10-79
26. 11039/6/77—अ. भा. से. (I)-बी तारीख 19-3-83
27. 14015/39/85—अ. भा. से. (I) तारीख 30-12-87
28. 13013/1/89—अ. भा. से. तारीख 24-1-89

[संख्या 14015/26/89—अ. भा. से. (I)]
एम. के. वेहन, टेस्क अधिकारी

MINISTRY OF PERSONNEL PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 1989

G.S.R. No. 967(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) and in pursuance of sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, the Central Government after consultation with the State Governments and the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, namely:—

1.(1) These regulations may be called the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Second Amendment Regulations, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955,—

(1) after clause (k) of sub-regulation (1) of regulation 2, the following clause shall be inserted, namely:—

“(1) ‘Year’ means the period commencing on the first day of April and ending on the 31st day of March of the subsequent year.”;

* (2) in regulation 3. for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

(1) There shall be constituted for a State Cadre or a joint cadre, a Committee consisting of the Chairman of the Commission or, where the Chairman is unable to attend, any other Member of the Commission representing it and the following other members namely:—

(a) For States other than Joint Cadres :

(i) Chief Secretary,

(ii) Officer not below the rank of Secretary to the Government Incharge of Home Department;

(iii) Director-General and Inspector-General of Police;

Where no Cadre post of Director-General and Inspector General of Police exists, then the Inspector-General of Police;

(iv) A member of the Service not below the rank of Deputy Inspector-General of Police; and

(v) A nominee of the Government of India not below the rank of Joint Secretary.

(b) For Joint Cadres other than Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories :

(i) Chief Secretaries to the Governments of the Constituent States;

(ii) Director-General and Inspector-General of Police of the Constituent States;

OR

Where no cadre post of Director-General and Inspector-General of Police exists then, the Inspector-General of Police of the Constituent States;

(iii) A nominee of the Government of India not below the rank of Joint Secretary.

NOTE : The position of the Committee for the Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories will be determined separately in consultation with the Joint Cadre Authority for the said Cadre.”;

(3) In regulation 5,—

(a) for the words “first day of January” wherever they occur, the words “first day of April” shall be substituted;

(b) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) Each Committee shall ordinarily meet at intervals not exceeding one year and prepare a list of such members of the State Police Service, as are held by them to be suitable, for promotion to the Service. The number of members of the State Police Service to be included in the list shall be calculated as the number of substantive vacancies anticipated in the course of the period of 12 months, commencing from the date of preparation of the list, in the posts available for them under rule 9 of the Recruitment Rules plus twenty per cent of such number or two whichever is greater.

EXPLANATION—In case of joint cadres, a separate select list shall be prepared in respect of each State Police Service, the size of each select list being determined in the manner indicated above.”

(c) sub-regulation (2A) and explanation thereunder shall be omitted;

(d) In sub-regulation (5), for the words “the State Police Service” the following shall be substituted, namely:—

“the State Police Service :

Provided that the name of any officer so included in the list shall be treated as provisional if the State Government, withholds the integrity certificate in respect of such officer or any proceedings are contemplated or pending against him or anything adverse against him has come to the notice of the State Government.”;

4. After regulation 6, the following regulation shall be inserted, namely:—

“6A. The State Government shall also forward a copy of the list referred to in regulation 6 to the Central Government and the Central Government shall send their observations on the recommendations of the Committee to the Commission.”;

5. In regulation 7,—

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely :

“(1) The Commission shall consider the list prepared by the Committee alongwith—

(a) the documents received from the State Government under regulation 6;

(b) the observations of the Central Government and unless it considers any change necessary, approve the list.”;

(b) in sub-regulation (4),—

(i) before the first proviso, the following shall be inserted, namely :—

“Provided that no appointment to the Service under regulation 9 shall be made after the meeting of the fresh Committee to draw up a fresh list under regulation 5 is held”;

(ii) in the first proviso, for the words “Provided that”, the words “Provided further that” shall be substituted;

6. In regulation 9,—

(a) in sub-regulation (1), after the proviso, the following provisos shall be inserted, namely:—

“Provided further that the appointment of an officer, whose name has been included in the select list provisionally, under proviso to sub-regulation (5) of regulation 5 shall be made after his name is made unconditional by the Commission on the recommendations of the State Governments during the period the Select List remains in force. While making appointment of an officer junior to a select list officer whose name has been included provisionally in the select list, one post will

have to be kept vacant for such a provisionally included officer;

Provided also that in case where a select list officer whose turn for appointment has come, has expressed his unwillingness for appointment to the service and the State Government concerned informs the Central Government accordingly, his juniors from the select list shall be appointed without keeping any post reserved for such an officer. He shall have no claim for appointment to the service from that select list.”;

(b) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before such appointments are made, unless during the period intervening between the inclusion of the name of a member of the State Police Service in the Select List and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in the work of the member of the State Police Service or there is any other ground which, in the opinion of the State Government or the Central Government, is such as to render him unsuitable for appointment to the service.”;

(7) after regulation 9, the following shall be inserted, namely:—

“9A. Powers of the Central Government not to appoint in certain cases.—

Notwithstanding anything contained in these Regulations or the recommendations made by the State Government concerned under Regulation 9(1). The Central Government may not appoint any person whose name appears in the Select List, if it is of opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest;

Provided that no such decision shall be taken by the Central Government without consulting the Union Public Service Commission”;

(8) the Schedule shall be omitted.

Note: The Principal Regulations were published vide Notification No. 14/2/54-AIS.II dated 6-6-1955.

Subsequently amended by:—

1. 13/21/56-AIS.III dated 28-2-58.
2. 13/10/57-AIS(III)-D dated 29-7-1958.
3. 17/19/58-AIS.III-B dated 2-6-1959.
4. 10/5/61-AIS.I dated 1-9-61.
5. 27/48/64-AIS III-11 dated 11-12-64.
6. 27/28/64-AIS. B dated 24-5-69.
7. 14/25/65-AIS. III dated 7-2-66.
8. 27/42/64-AIS. III dated 31-3-67.
9. 13/4/67-AIS(I)-(5) dated 29-12-67.
10. 17/5/68-AIS. III-B dated 24-5-69.
11. 17/19/58-AIS(III)B dated 2-6-69.
12. 16/1/68-AIS (III) dated 9-4-70.
13. 16/5/70-AIS (III) dated 21-9-71.
14. 13/4/71-AIS(I) dated 11-1-72.
15. 1/1/72-AIS(I)-B dated 12-10-72.
16. 11/1/72-AIS(I)-B dated 22-5-73.
17. 11/2/73-AIS(I)-D dated 12-9-73.
18. 11/1/73-AIS(I)-B dated 19-2-74.
19. 11039/6/75-AIS(I)-B dated 20-4-76.
20. 11039/6/75-AIS(I)-B dated 30-9-76.
21. 11039/6/76-AIS(I)-B dated 11-4-77.
22. 11039/6/76-AIS(I)-A dated 3-6-77.
23. 11039/2/76-AIS(I)-A dated 3-10-77.
24. 11039/21/76-AIS(I)-B dated 1-6-78.
25. 28013/20/76-AIS(I)-B dated 5-10-79.
26. 11039/6/77-AIS(I)-B dated 19-3-83.
27. 14015/39-85-AIS(I) dated 30-12-87.
28. 130/13/189-AIS(I) dated 24-1-89.

[No. 14015/26/89-AIS(I)]

M. K. TREHAN, Desk Officer.

